भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की क्रय और विक्रय दरें

2375. श्री रामजीलाल: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किसानों को अनाज का कितना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और भारतीय खाद्य निगम इसकी किस दर पर बिक्री करता है;

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम की कुल क्षमता 7.89 लाख टन है और इसकी उपयोगिता 50% है।

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव है कि धामत्री में 10,000 टन क्षमता का निर्माण किया जाए जिसके 1997-98 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य नियम ने हरियाणा में अनाज की किस-किस दर पर खरीद और बिक्री की है;

(ग) इससे भारतीय खाद्य निगम ने कुल कितना लाभ कमाया;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम साफ और अच्छी किस्म का अनाज खरीदता है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के अनाज में धूल और कूड़ा मिला होने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) (क) और (ख) केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और धान की वसूली न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर की जाती है। ये मूल्य हरियाणा सहित देश भर में एक समान हैं। पिछले तीन विपणन मौसमों के लिए गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य			
	गेहूं	धान		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
1994-95	350	340	360	380
1995-96	360	360	375	395
1996-97	380	380	395	415

केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल देश भर में एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) जारी किए जाते हैं। गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से प्रभावी	केन्द्रीय निर्गम मूल्य			
प्रभावी	गेहूं	चावल		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
1.2.1994	402	537	617	648

1.2.1994 के पश्चात् गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है।

(ग) केन्द्रीय निर्गम मूल्य खाद्यान्नों की इक्रामिक लागत को पूर्णतया पूरा नहीं करते हैं और भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की इक्रामिक लागत तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच अंतर को सरकार द्वारा खाद्य राजसहायता वहन करके पूरा किया जाता है। अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा इससे कोई लाभ प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम निर्धारित की गई विनिर्दिष्टयों के अनुरूप खाद्यान्न खरीदता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के अधीन वितरित करने के लिए उन्हें राज्य सरकारों/उनके नामितियों को जारी करता है। वे स्टाक की सुपुर्दगी केवल तभी स्वीकार करते हैं जब वे इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि स्टाक उचित औसत किस्म का है।

Revival of BPMEL

2376. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to Starred Qestion 514 answered in Rajya Sabha on 9th September, 1996 and state:

(a) the total revival cost of Bharat Process & Mechanical Engineers Limited as worked cut by the consultant;

(b) fund generated through sale of dispensable assets;

(c) funding required from the Government after converting the outstanding loans into equity and writing off the interest;

(d) whether an appeal from the employees against the BIFR order has been admitted by the Appallate Authority for Industrial and Financial Reconstruction;

(e) If so, the observations of the Appellate Authority; and

(f) action contemplated by the Government for revival of this company?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) According to consultant's report, the cost of the scheme is Rs. 15.40 crore, out of which Rs. 4.32 crore is to be financed through disposal of assets.

(c) According to the consultant, the requirement of funds from the Government is Rs. 9.60 crore, which will remain unchanged even if outstanding Government loan is converted into equity & interest is written off.

(d) to (f) The appeal has been admitted by AAIFR on 13.11.96 and the next hearing has been scheduled for 6.1.1997. Further action will be taken as warranted by the decision of AAIFR.

Mismanagement in BCCL

2377. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news-item which appeared in the Economic Times dated 21st October, 1996 under the caption "A roundabout strategy for Bharat Coking";

(b) if so, the reaction of the Government on each of the points mentioned in the news-item and action being contemplated to correct the situation;

(c) the extent to which the reported/ suggested shortages in coal stocks of BCCL, year, have contributed to the present situation of BCCL;

(d) whether any responsibilities have been fixed for the reported and other mismanagements in BCCL which have brought the BCCL to its current situation, and action taken against them; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) One of the specific points raised in the article is that certain high-tech mines